



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 373]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 22, 2018/अग्रहायण 1, 1940

No. 373]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 22, 2018/AGRAHAYANA 1, 1940

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2018

(अंतिम जांच परिणाम)

न्यू शिपर समीक्षा को समाप्त करना

विषय – बंगलादेश और नेपाल के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "जूट उत्पादों" अर्थात् जूट यार्न/ट्विन (बहुविद मोड़े गए/केबिल युक्त तथा एकल), हैसियन फैब्रिक और जूट सैकिंग बैगों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के मामले में मैसर्स अमन जूट फाइब्रस लिमिटेड (उत्पादक) और मै. आई बी जूट कॉर्पोरेशन (निर्यातक/व्यापारी) के लिए अलग-अलग पाटन मार्जिन निर्धारित करने हेतु पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 के तहत न्यू शिपर समीक्षा।

क. पृष्ठभूमि :

फा.सं. 7/23/2017-डीजीएडी.— बंगलादेश से संबद्ध सामानों के उत्पादक/निर्यातक मै. अमन जूट फाइब्रस (उत्पादक) तथा मै. आई बी जूट कॉर्पोरेशन (निर्यातक/व्यापारी) (जिन्हें यहां आगे "आवेदक" कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे यहां आगे "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे यहां आगे अधिनियम कहा गया है) तथा समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 के अनुसार एक आवेदन दायर किया है जिसमें उन्होंने बंगलादेश और नेपाल के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "जूट उत्पादों" के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के मामले में उनके लिए अलग-अलग

पाटन मार्जिन निर्धारित करने के लिए अनुरोध किया है। उपर्युक्त शुल्क मूल पाटनरोधी मामले में दिनांक 20 अक्टूबर, 2016 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 14/19/2015-डीजीएडी तथा दिनांक 5 जनवरी, 2017 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 01/2017-सीमाशुल्क (एडीडी) और दिनांक 3 अप्रैल, 2017 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 11/2017-सीमाशुल्क (एडीडी) द्वारा लगाए गए थे।

2. जबकि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह न्यू शिपर समीक्षा जांच 23.1.2018 को शुरू की। तदनुसार, केन्द्र सरकार ने दिनांक 30.5.2018 की अधिसूचना सं. 31/2018-सीमाशुल्क (एडीडी) जारी की।

ख. विचाराधीन उत्पाद

3. विचाराधीन उत्पाद वही है जो मूल जांच में है जिसे निम्नलिखित रूप में वर्णित किया गया है।

“जूट यार्न/ट्विन (बहुविद मोडे गए/केबिल युक्त तथा एकल), हैसियन फैब्रिक और जूट सैकिंग बैगों से युक्त “जूट उत्पाद””

प्राधिकारी ने उत्पादकों के लिए मूल जांच में जूट उत्पादों की प्रत्येक किस्म के लिए पृथक शुल्क की सिफारिश की थी।

ग. जांच की अवधि

4. वर्तमान समीक्षा के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि 1 जुलाई, 2017 से 30 सितम्बर, 2018 है।

घ. घरेलू उद्योग और आवेदक/निर्यातक द्वारा अनुरोध

5. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

i. अनुरोध है कि नियम 22 के तहत निर्धारित शर्तों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान न्यूशिपर समीक्षा उपयुक्त नहीं है। नियम 22 के तहत आवेदकों को प्राधिकारी द्वारा पूर्व में विचार की गई जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का किसी भी रूप में निर्यात नहीं करना चाहिए था। उस अवधि में विचाराधीन उत्पाद के किसी भी रूप का निर्यात ऐसी कंपनियों को न्यू शिपर समीक्षा तथा अलग-अलग पाटन मार्जिन के स्तर का दावा करने से अपात्र होना चाहिए। चूंकि प्राधिकारी ने मूल मामले में नमूने का सहारा लिया है अतः इन कंपनियों को पाटन मार्जिन और मूल जांचों की सहयोगी गैर-नमूना कंपनियों को दिए गए/निर्धारित किए गए पाटनरोधी शुल्क दिया जा सकता है।

ii. नियम 22 के तहत अलग-अलग पाटन मार्जिन के दावे का अर्थ यह नहीं है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए उनके अपने सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के आधार पर इन निर्यातकों को पाटन मार्जिन देना अनिवार्य है। यह अनुरोध किया जाता है कि नियम 17 के अनुसार प्राधिकारी के लिए प्रत्येक ज्ञात निर्यातक/उत्पादक हेतु पाटन का अलग मार्जिन निर्धारित करना अपेक्षित है। यह दायित्व नियम 22 के तहत दायित्व के समान है क्योंकि दोनों नियमों में निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रत्येक ज्ञात निर्यातक के लिए अलग-अलग पाटन मार्जिन निर्धारित करना अपेक्षित है। नियम 17 और नियम 22 की तुलना करने के बाद यह देखा जाएगा कि नियम 17 के तहत निर्यातक अपने पाटन मार्जिन के हकदार हैं। तथापि, नियम 17 के तहत निर्यातकों के लिए उपलब्ध अधिकार नियम 17 के तहत नमूने के आगे प्रावधान द्वारा रद्द/योग्य/समाप्त/खत्म हो जाते हैं जिसमें निम्नलिखित प्रावधान है।

..... बशर्ते कि ऐसे मामलों में जहां शामिल निर्यातकों, उत्पादकों और आयातकों अथवा वस्तुओं की किस्मों की संख्या इतनी अधिक है कि उनका निर्धारण किया जाना अव्यवहारिक होता है, तो ऐसी स्थिति में वह सांख्यिकीय रूप से वैध प्रतिदर्शों का उपयोग करके अपने निष्कर्षों में उसकी सीमा, हितबद्ध पक्षकारों अथवा वस्तुओं की उचित संख्या तक तय कर सकते हैं, जो कि ऐसे चयन के समय उपलब्ध सूचना के आधार पर होगी अथवा संबंधित देश से निर्यातों की मात्रा के सबसे

अधिक प्रतिशत पर ऐसा चयन कर सकते हैं, जिसकी उचित रूप से जांच की जा सकती हो और इस परन्तु के अंतर्गत निर्यातकों, उत्पादकों अथवा वस्तुओं की किस्मों का किया गया चयन, अधिमानतः संबंधित निर्यातकों, उत्पादकों अथवा आयातकों के परामर्श से किया जाए।”

- iii. अनुरोध है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए प्रत्येक ज्ञात न्यू शिपर के लिए अलग-अलग पाटन मार्जिन निर्धारित करना अपेक्षित है। यह दायित्व अलग-अलग पाटन मार्जिन निर्धारित करने के लिए ही है न कि अलग-अलग सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करने के लिए। यह पाटन मार्जिन के निर्धारण तथा नमूना दोनों के लिए नियम 17 की भाषा द्वारा स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जाता है। यह आवेदन प्राधिकारी पर भार सृजित कर रहा है। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना के अनुसार बंगलादेश में विचाराधीन उत्पाद के लगभग 285 उत्पादक हैं। उत्पाद को 3 श्रेणियों में अलग-अलग बांटने के बाद निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अलग-अलग पाटन मार्जिन का दावा करने के लिए बंगलादेश में पुनः उत्पादन के लिए छूट प्रदान की है, यदि उन्होंने किसी अलग उत्पाद का निर्यात नहीं किया है। इस प्रकार बंगलादेश में उत्पाद श्रेणियों और उत्पादकों की संख्या पर विचार करते हुए लगभग 855 संभावित संयोजन हैं जिनमें भारत को सामानों का निर्यात किया गया है। इन चैनलों का मूल जांचों की जांचावधि में प्रयोग नहीं किया गया था और इसीलिए संभवतः चैनलों की बहुत अधिक संख्या है जो भारत को निर्यात के लिए उपलब्ध हैं। इस प्रकार प्राधिकारी को चुनिन्दा कुछ पक्षकारों के निर्यात मूल्य और निर्यात कीमत के परिकलनों के लिए अलग-अलग पाटन मार्जिन प्रतिबंधित करने हेतु नमूने की अनुमति देने का प्रावधान तथा उसके बाद सभी अन्य सहयोगी निर्यातकों को वहीं रखने के लिए सहयोगी न्यू शिपरों पर भी लागू होना चाहिए।
- iv. अनुरोध है कि नियम 22 में समय-समय पर अलग-अलग पाटन मार्जिन निर्धारित किए जाने का प्रावधान है। इस प्रावधान को पढ़ने से यह बात भी सामने आती है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी कोई आवेदन हर समय किए जाने पर समीक्षा करने के लिए बाध्य नहीं है। “समय-समय पर” शब्द को पढ़ने से ऐसे आवेदन पत्रों को मिलाने और उसके बाद अलग-अलग पाटन मार्जिन निर्धारित का स्पष्ट संकेत मिलता है। यह केवल न्यू शिपर की हकदारी तथा पूर्व में निर्धारित पाटन मार्जिन के आधार पर पाटन मार्जिन देने को सिद्ध करने की संभावना भी दर्शाता है।
- v. अनुरोध है कि बंगलादेश में उत्पादक यह तर्क दे सकते हैं कि उन्हें यदि उनके सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के आधार पर पाटन शुल्क हैं तो उन्हें उच्चतर पाटन शुल्क के अध्वधीन रखा जाएगा। तथापि, यह तर्क उन गैर-नमूनायुक्त सहयोगी उत्पादकों के लिए भी अच्छा हो सकता है जिन्होंने प्राधिकारी के साथ सहयोग नहीं किया और पाटन मार्जिन के अलग-अलग निर्धारण के लिए जिन पर विचार नहीं किया गया था। यदि इन गैर नमूना युक्त सहयोगी उत्पादकों के अधिकार नमूना प्रावधान की दृष्टि से कम किए जाते हैं तो यह आवश्यक नहीं है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी इन न्यू शिपरों के लिए उनके अपने अलग-अलग सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के आधार पर पाटन मार्जिन निर्धारित किया जाना चाहिए। उन्हें वही समान पाटन मार्जिन देना उपयुक्त होगा जो कि बंगलादेश के अन्य गैर-नमूना युक्त सहयोगी निर्यातकों के लिए निकाला गया है।
- vi. प्रस्ताव है कि मूल जांचों के समय सहयोगी गैर-नमूनायुक्त उत्पादक न्यू शिपर की तुलना में नुकसान में नहीं हो सकते। सहयोगी गैर-नमूनायुक्त उत्पादकों में प्राधिकारी को उत्तर भी दिया था और अलग-अलग पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए पूरा सहयोग भी दिया था। तथापि, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने उनके आंकड़ों के आधार पर पाटन मार्जिन निर्धारित करने का निर्णय नहीं लिया। जिस पक्षकार ने मूल अवधि के दौरान निर्यात नहीं किया, उसका स्तर उस पक्षकार के स्तर की तुलना में अधिक अलाभप्रद नहीं हो सकता जिसने संगत अवधि के दौरान निर्यात किया और

- प्राधिकारी के साथ सहयोग किया परंतु, नमूना कानून की दृष्टि से उनके अपने आंकड़ों के आधार पर पाटन मार्जिन इंकार कर दिया गया।
- vii. यह तर्क दिया जाता है कि उनके अपने सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के आधार पर अलग-अलग पाटन मार्जिन प्रदान न करने से बड़ा हुआ पाटन मार्जिन हो सकता है तथा इन निर्यातकों को उस पाटनरोधी शुल्क की अधिक राशि देनी पड़ सकती है जोकि देय होती, यदि उनके अपने आंकड़ों पर प्राधिकारी ने विचार किया होता। तथापि, यह स्थिति मूल जांच में नमूने के मामले में भी स्पष्ट रूप से मौजूद है जिसका यह अभिप्राय है कि नमूना कानून गैर-कानूनी है। तथापि, ऐसी स्थिति में जहां निर्यातक को अपने पाटन मार्जिन से अधिक शुल्क देने की आवश्यकता है, स्पष्ट रूप से समीक्षा कानूनों में हल की गई है। यदि कोई निर्यातक यह महसूस करता है कि उसे उनके अपने आंकड़ों में पाटन मार्जिन से अधिक पाटनरोधी शुल्क देने के लिए निर्धारित किया गया है, तो ऐसे निर्यातक समीक्षा का दावा करने और लिए गए ऐसे पाटनरोधी शुल्क की वापसी के हकदार हैं।
- viii. इस पर भी विचार करना संगत है कि किसी निर्यातक पर लगाया गया पाटनरोधी शुल्क वर्तमान निर्यात लेनदेनों में मौजूद होने वाले पाटन मार्जिन से अधिक अथवा कम हो सकता है। यद्यपि, जांच की अवधि के आंकड़ों के आधार पर पाटन मार्जिन सिद्ध हो जाता है तथापि, यह पूर्णतः संभव है कि वर्तमान निर्यातों में पाटन मार्जिन निर्यातकों के लिए निर्धारित पाटनरोधी शुल्क और पाटन मार्जिन से कम अथवा अधिक है। तथापि, यदि वह पाटन मार्जिन दिए गए पाटन मार्जिन और पाटनरोधी शुल्क से कम है तो निर्यातक समीक्षा के माध्यम से उसकी वापसी की मांग करने के हकदार हैं। इसके अतिरिक्त घरेलू उद्योग मध्यावधि समीक्षा की मांग करने तथा पाटन मार्जिन बढ़ाने का अनुरोध करने के भी हकदार हैं। तथापि, यदि वर्तमान पाटन मार्जिन मूल जांच में निर्धारित पाटन मार्जिन से अधिक है तो घरेलू उद्योग के पास समीक्षा की अवधि के लिए नुकसान उठाने के लिए कोई विकल्प नहीं है। इसके विपरीत, निर्यातक पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा की मांग कर सकते हैं और आयातक शुल्क वापसी ले सकते हैं। इस प्रकार, निर्यातकों के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं हुआ है।
- ix. यह अनुरोध है कि मूल जांच के दौरान निर्दिष्ट प्राधिकारी ने उत्तरदाता निर्यातकों द्वारा किए गए निर्यातों के आधार पर नमूनाकरण का सहारा लिया है जो यह सिद्ध करता है कि आयात मात्रा का संबंध और महत्व न्यू शिपर समीक्षा मामले के लिए कम नहीं किया जा सकता। इस स्तर पर प्राधिकारी उस आयात मात्रा पर कृपया विचार करें और तुलना करें जो उत्तरदाता निर्यातकों ने सूचित की है और उसकी उस आयात मात्रा से तुलना करें जो मूल जांचों के समय उत्तरदाता निर्यातकों द्वारा सूचित की गई थी। यह देखा जाएगा कि इन कंपनियों द्वारा किए गए निर्यातों की मात्रा उन निर्यातों की मात्रा की तुलना में काफी कम है जिन पर अलग-अलग प्रश्नावली के उत्तर के आधार पर अलग-अलग सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत निर्धारित करने के लिए विचार किया गया था। इस प्रकार, प्राधिकारी के लिए निर्यातक के अलग-अलग प्रश्नावली के उत्तर तथा संबंधित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के आधार पर अलग-अलग पाटन मार्जिन निर्धारित करना आवश्यक नहीं है।
- x. अनुरोध है कि चूंकि निर्यात कीमत वह कीमत है जिस पर भारतीय बाजार में खपत के लिए सामानों का निर्यात किया गया है। अतः जिस कीमत पर भारत में विभिन्न क्रेताओं ने बंगलादेश से विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से सामानों की खरीद की है, वह वास्तविक रूप से भिन्न नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए यदि एक बंगलादेशी उत्पादक 1000 अम.डॉ./ मी.ट. की कीमत पर बिक्री कर

रहा है तो उपभोक्ता इस कीमत से वास्तविक रूप से अधिक कीमत पर किसी अन्य आपूर्तिकर्ता से उत्पाद नहीं खरीदेगा। इस प्रकार, विभिन्न निर्यातकों की निर्यात कीमत में वास्तविक अंतर नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त, बंगलादेश की भौगोलिक स्थिति, भारतीय पत्तनों से बंगलादेश के अलग-अलग संयंत्रों के स्थान पर विचार करते हुए उन खर्चों में वास्तविक अंतर नहीं हो सकता जो बंगलादेश में विभिन्न उत्पादकों ने किए हैं। इस प्रकार, सामान्य प्रतिस्पर्धी स्थितियों में विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं की निर्यात कीमत में वास्तविक अंतर नहीं हो सकता।

- xi. उपर्युक्त के मद्देनजर घरेलू उद्योग का अनुरोध है कि प्राधिकारी को उस निर्धारण के लिए वर्तमान जांचों के परिणामों को प्रतिबंधित करना चाहिए भले ही उत्तरदाता निर्यातक नियम 22 के अभिप्राय से न्यू शिपर में आते हों। यदि समीक्षा की मांग करने वाले निर्यातक नियमावली के अभिप्राय से “न्यू शिपर” हैं, तो प्राधिकारी सहयोगी गैर-नमूना युक्त उत्पादकों के लिए पूर्व में निर्धारित भारित औसत पाटन मार्जिन के रूप में पाटन मार्जिन निर्धारित कर सकते हैं। उपर्युक्त पाटन मार्जिन उल्लिखित स्तरों से कम पर निर्धारित किया गया था और इसीलिए हम प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वे कृपया एन एस आर की अपेक्षा और इन पक्षकारों के दायित्वों की पूर्ति के अध्यधीन इन न्यू शिपर कंपनियों के लिए शुल्क की यह मात्रा निर्धारित करे। तथापि, यदि ये पक्षकार किसी हालत में एनएसआर की अपेक्षाओं को पूरा करने में विफल रहते हैं तो वे इन पाटन मार्जिन के भी हकदार नहीं होंगे और इन पक्षकारों पर पूर्व में लगाए गए अवशिष्ट शुल्क से अलग किया जाना चाहिए।

पाटन मार्जिन (सहयोगी गैर नमूना उत्पादक) और शुल्क स्तर दर्शाने वाली तालिका

वस्तुओं का विवरण	उत्पादक	निर्यातक	पाटन मार्जिन रेंज (%)	क्षति मार्जिन रेंज (%)	शुल्क राशि
जूट यार्न /टिन्स	गैर-नमूना उत्पादक/निर्यातक		10-20	20-30	97.19 अम.डॉ./मी.ट.
सैकिंग बैग	गैर-नमूना उत्पादक/निर्यातक		10-20	10-20	351.72 अम.डॉ./मी.ट.
हैसियन फैब्रिक	गैर-नमूना उत्पादक/निर्यातक		60-70	40-50	125.21 अम.डॉ./मी.ट.

6. आवेदक/उत्पादक द्वारा किए गए अनुरोध निम्नलिखित हैं :

- घरेलू उद्योग ने अनिवार्य रूप से यह दावा किया है कि प्राधिकारी को निर्धारण के लिए वर्तमान एनएसआर जांच के परिणाम को प्रतिबंधित करना चाहिए भले ही उत्तरदाता निर्यातक नियम 22 के अभिप्राय से न्यू शिपर हों तथा यदि समीक्षा की मांग करने वाले निर्यातक नियमावली के अभिप्राय से “न्यू शिपर” हैं तो प्राधिकारी सहयोगी गैर-नमूना उत्पादकों के लिए पूर्व में निर्धारित भारित औसत पाटन मार्जिन के रूप में पाटन मार्जिन निर्धारित कर सकते हैं। विनम्र अनुरोध है कि यह प्रस्ताव न्यू शिपर समीक्षा के मौलिक सिद्धांतों के विरुद्ध है जैसा कि डब्ल्यू टी ओ पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 9.5 और भारतीय पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 में भी प्रावधान है।
- उपर्युक्त करार और नियम स्पष्ट रूप से प्रश्नगत उस निर्यातक देश में निर्यातकों अथवा उत्पादकों के लिए अलग-अलग पाटन मार्जिन बताता है जिन्होंने जांच की अवधि के दौरान भारत में उत्पाद का निर्यात नहीं किया है बशर्ते कि प्रावधान हों। इस प्रकार, अलग-अलग मार्जिन नए सिरे से निर्धारित किया जाना चाहिए और उन उत्पादकों पर पुराना मार्जिन नहीं लगाया जा सकता।

घरेलू उद्योग की यह अवधारणा कि न्यू शिपर को नकारात्मक पाटन मार्जिन मिल सकता है अथवा निर्यातकों की गैर-नमूना श्रेणी अलाभप्रद स्थिति में हो सकती है, न्यू शिपर समीक्षा के मूलभूत पहलू से अलग होने का आधार नहीं हो सकती जोकि नियमावली में परिभाषित किए गए अनुसार न्यू शिपरों के लिए अलग-अलग पाटन मार्जिन का निर्धारण है।

- iii. मूल जांच में किया गया नमूनाकरण उस समय जांच के भार की परिस्थितियों के आधार पर था और वर्तमान न्यू शिपरों के लिए तत्कालीन नमूना युक्त श्रेणियों में निर्धारित भारित औसत मार्जिन लेना पूर्णतः प्राधिकारी को भ्रमित करने तथा जांच को धीमा करने का तर्क है।
- iv. न्यू शिपर प्राधिकारी के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं और अनुरोध है कि प्राधिकारी द्वारा केवल संबंधित न्यू शिपरों पर लागू सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के अनुसार अलग-अलग पाटन मार्जिन निर्धारित किए जाएं।

7. आवेदन पत्र वापस लेना:

- i. आवेदक (निर्यातक) ने अपने दिनांक 10.10.2018 के पत्र द्वारा यह अनुरोध किया कि कुछ कठिनाइयां हैं जिनके कारण सामानों के हमारे निर्यातों में भारत में विचार के तहत बाधा आती है। कंपनी के प्रोपराइटर 5.7.2018 से 25.9.2018 तक अस्पताल में थे और वह व्यक्ति उस समय के दौरान सामान्य रूप से कोई व्यापार नहीं कर पाया। उपर्युक्त चिकित्सा स्थिति के कारण समय बर्बाद होने के मद्देनजर, जिसके दौरान जांच की शुरुआत के अनुसार भारत को सामानों का कोई निर्यात नहीं किया गया, हम प्राधिकारी से जांच की शुरुआत की अधिसूचना में संशोधनों के साथ जांच की अवधि अगले 6 माह से 30 सितंबर, 2018 तक बढ़ाने का अनुरोध करते हैं ताकि हम अगले 6 माह तक उन शर्तों के अनुसार भारत को सामानों का निर्यात कर सकें।
- ii. आवेदक (निर्यातक) ने अपने दिनांक 9.11.2018 के पत्र द्वारा यह अनुरोध किया कि जांच की अवधि के दौरान कोई निर्यात न होने के मद्देनजर हम एतद्वारा अपने एनएसआर आवेदन को वापस लेते हैं। हम समझते हैं कि आवेदन पत्र वापस लेने से निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा मामले को समाप्त किया जाएगा जिस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। फिर भी, हमें भविष्य में माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध करने का अधिकार है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

8. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि, घरेलू उद्योग ने आवेदक उत्पादक/निर्यातक के लिए नियम 22 की पात्रता और प्रयोज्यता के संबंध में अनुरोध किए हैं, तथापि, उनका समाधान नहीं किया जा रहा है क्योंकि आवेदक उत्पादक/निर्यातक ने आवेदन पत्र वापस ले लिया है।
9. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विभिन्न “जूट उत्पादों” अर्थात् जूट यार्न/ट्विन (बहुविद मोड़े गए/केबिल युक्त तथा एकल), हैसियन फैब्रिक और जूट सैकिंग बैगों के संबंध में न्यू शिपर समीक्षा मैसर्स अमन जूट फाइब्रस लिमिटेड (उत्पादक) और मै. आई बी जूट कॉर्पोरेशन (निर्यातक/व्यापारी) के लिए जांच की अवधि 1 जुलाई, 2017 से 30 सितंबर, 2018 तक के लिए 23.1.2018 को शुरू की गई थी।
10. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सक्षम सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 31/2018-सीमाशुल्क-एडीडी, 30.5.2018 को जारी की गई थी। तथापि, आवेदक उत्पादक/निर्यातक ने न तो जांच की ऐतिहासिक अवधि के दौरान और न ही संभावित जांच की अवधि के दौरान निर्यात किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह उल्लेख किया गया है कि निर्यातक अपनी चिकित्सा हालत के कारण निर्यात करने में असमर्थ था। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि उत्पादक/निर्यातक को संबद्ध सामानों का कुछ उपयुक्त निर्यात करने के लिए पर्याप्त थी भले ही ऐसी अपरिहार्य स्थितियां बन गई हों। प्राधिकारी की यह परिपाटी नहीं है कि वे जांच की अवधि के अंतिम स्तर पर किसी एनएसआर जांच में जांच की अवधि बढ़ाएं।

11. याचिका की स्पष्ट वापसी के मद्देनजर प्राधिकारी मौखिक सुनवाई करने और प्रकटन जारी करना उपयुक्त नहीं समझते जोकि निरर्थक प्रतीत होता है।
12. प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादक/निर्यातक ने अपने वापसी के पत्र दिनांक 19.11.2018 में यह उल्लेख किया है कि वे इसी अनुरोध के साथ बाद की तारीख में प्राधिकारी से अनुरोध कर सकते हैं।
13. प्राधिकारी आवेदक, उत्पादक/निर्यातक के अनुरोध तथा अन्य संगत अनुरोधों को नोट करते हैं और निम्नलिखित सिफारिश करते हैं :
 - (i) आवेदक मैसर्स अमन जूट फाइब्रस लिमिटेड (उत्पादक) और मै. आई बी जूट कॉर्पोरेशन (निर्यातक/व्यापारी) ने जांच की अवधि के दौरान किसी संबद्ध सामान का निर्यात नहीं किया है।
 - (ii) उपर्युक्त (i) के मद्देनजर आवेदक, उत्पादक/निर्यातक के लिए किसी अलग मार्जिन की सिफारिश नहीं की जा सकती।
 - (iii) अतः प्राधिकारी उपर्युक्त उत्पादक/निर्यातक के लिए 23.1.2018 को शुरू की गई इस एनएसआर जांच को रद्द करते हैं। उत्पादक/निर्यातक यदि चाहें तो संगत पाटनरोधी नियमावली के प्रावधानों के अनुसार नए सिरे से एनएसआर दायर कर सकते हैं।
 - (iv) उत्पादक/निर्यातक वर्तमान मामले के अनुसार अवशेष श्रेणी के तहत दिनांक 3.4.2017 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 11/2017-सीमाशुल्क(एडीडी) के अनुसार निर्धारित किए जाते रहेंगे।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd November, 2018

(Final Finding)

Termination of the NSR

Subject: New Shipper Review under Rule 22 of the Anti-Dumping Rules for determination of individual dumping margin for M/s Aman Jute Fibrous Ltd. (Producer) and M/s IB Jute Corporation (Exporter/Trader) in the case of Anti-dumping duty imposed on “Jute Products” viz – Jute Yarn/ Twine (multiple folded/cabled and single), Hessian Fabric and Jute Sacking Bags originating in or exported from Bangladesh and Nepal.

A. BACKGROUND:

F. No. 7/23/2017-DGAD.—M/s Aman Jute Fibrous Ltd. (Producer) and M/s IB Jute Corporation (Exporter/Trader) (hereinafter referred to as the “Applicants”), a producer/exporter of the subject goods from Bangladesh has filed an application in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 (hereinafter referred to as the Act) as amended from time to time and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti- Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter referred to as the AD Rules) before the Designated Authority (hereinafter referred to as the “Authority”) requesting for determination of their individual dumping margin in the matter of anti-dumping duties levied on imports of “Jute Products” originating in or exported from Bangladesh and Nepal. The said duties were imposed vide Final Findings Notification No. 14/19/2015-DGAD dated 20th October, 2016 and Customs Notification No. 01/2017 – Cus (ADD) dated

5th January, 2017 and Customs Notification No. 11/2017-Cus (ADD) dated 3rd April, 2017 in the original Anti-Dumping case.

2. Whereas, the Designated Authority initiated this NSR investigation on 23.1.2018. Accordingly, Central Government issued Notification No. 31/2018- Customs (ADD) dated 30.5.2018.

B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION:

3. The product under consideration is same as in the original investigation which is described as under:
“‘Jute Products’ comprising of Jute yarn/twine (multiple folded/cabled and single), Hessian Fabrics and Jute Sacking bags.”

The Authority had recommended separate duty for each type of Jute products in the original investigation to producers.

C. PERIOD OF INVESTIGATION:

4. The period of investigation for the purpose of the present review is 1st July, 2017 to 30th September, 2018.

D. SUBMISSIONS BY DOMESTIC INDUSTRY AND APPLICANT/EXPORTER:

5. The Submissions by Domestic Industry are as under:
 - i. It is submitted that the present new shipper review is not appropriate, having regard to the conditions prescribed under Rule 22. Under Rule 22, the applicants should not have exported the product under consideration in any of its form during the investigation period earlier considered by the Authority. Exports of any one form of the product under consideration in that period should disentitle such companies from claiming the status of new shipper review and individual dumping margin. Since the Authority had resorted to sampling in the original case, these companies can at best be given the dumping margin and ADD determined/given to cooperating non sampled companies of the original investigations.
 - ii. The Claim for individual dumping margin under Rule 22 does not imply that the DA is obliged to give dumping margin to these exporters on the basis of their own normal value and export price. It is submitted that as per Rule 17, the Authority is required to determine individual margin of dumping for each known exporter/producer. This obligation is similar to the obligation under Rule 22, as, under both the rules, the DA is required to determine individual margin of dumping for each known exporter. After comparing rule 17 and rule 22, it would be seen that under Rule 17, the exporters are entitled to their own dumping margin. However, the right available to exporters under Rule 17 gets superseded/ qualified/curtailed/suppressed by the further provision of sampling under Rule 17 which provides as follows.

“..... Provided that in cases where the number of exporters, producers, importers or types of articles involved are so large as to make such determination impracticable, it may limit its findings either to a reasonable number of interested parties or articles by using statistically valid samples based on information available at the time of selection, or to the largest percentage of the volume of the exports from the country in question which can reasonably be investigated, and any selection, of exporters, producers, or types of articles, made under this proviso shall preferably be made in consultation with and with the consent of the exporters, producers or importers concerned :”
 - iii. It is submitted that DA is required to determine individual dumping margin for each known new shipper. This obligation is only on determination of individual dumping margin and not on consideration of individual normal value and export price. This gets clearly established by the language of Rule 17 for both determination of dumping margin as well as sampling. This application is creating burden on the Authority. As per publicly available information, there are about 285

producers of the product under consideration in Bangladesh. Further, after sub-dividing the product into three categories, the DA has granted liberty to reproduces in Bangladesh to claim individual dumping margin if they have not exported any individual product. Thus, considering the product categories and number of producers in Bangladesh, there are about 855 possible combinations in which goods have been exported to India. These channels were not used in the POI of original investigations and therefore there is potentially a very high number of channels which are available for exports to India. Thus, the provision of sampling permitting the Authority to restrict individual dumping margins to calculations of normal value and export price of select few parties and thereafter putting the same to all other cooperating exporters should get applied to cooperating new shippers as well.

- iv. It is submitted that Rule 22 provides for determination of individual dumping margin from time to time. A reading of this provision further shows that the DA is not obliged to undertake a review every time an application has been made. The reading of the word “from time to time” is clearly indicative of bunching of such applications and thereafter determining individual dumping margins. This further shows a possibility of establishing only entitlement as a new shipper and thereafter giving dumping margin based on the dumping margin earlier determined.
- v. It is submitted that producers in Bangladesh may contend that they will be subjected to higher dumping duties if the dumping duties are not based on their own normal value and export price. However, the argument could hold good even for non-sampled cooperating producers who had also cooperated with the authority and were not considered for individual determination of dumping margin. If rights of these non-sampled cooperating producers got curtailed by virtue of sampling provisions, it is not necessary that the Designated Authority should determine dumping margin for these new shippers based on their own individual normal value and export price. It would be appropriate to give them the same dumping margin as has been worked out for other non-sampled cooperating exporters from Bangladesh.
- vi. It is proposed that the cooperating non-sampled producers at the time of original investigations cannot be at a disadvantage as compared to a new shipper. The cooperating non-sampled producers had also responded to the authority and had extended full cooperation for determination of individual dumping margin. The Designated Authority however decided not to determine dumping margin based on their data. Status of a party who did not export during the original period cannot be more advantageous as compared to status of the party who had exported during relevant period and had cooperated with authority but was denied dumping margin based on their own data by virtue of sampling law.
- vii. It is contended that non granting of individual dumping margin based on their own normal value and export price might lead to exaggerated dumping margin and these exporters may be made to pay a higher quantum of ADD as would have been payable, had that authority considered their own data. However, this situation clearly exists even in case of sampling in original investigations which in turn implies that the sampling law is illegal. However, in a situation where exporter needs to pay a duty higher than its own dumping margin is clearly addressed in the review laws. If any of the exporters feel that they have been made to pay a higher quantum of ADD than the dumping margin in their own data, such exporters are entitled to claim a review and refund of anti-dumping duty so collected.
- viii. It is also relevant to consider that the ADD that may be attracted by an exporter may be higher or lower than the dumping margin that might exists in the current export transactions. While the dumping margin gets established on the basis of POI data, it is quite possible that the dumping margin in the present exports is higher or lower than dumping margin and ADD determined for the exporter. However, if such dumping margin is lower than the dumping margin and ADD paid, the exporters are entitled to seek a refund through a review. Further, the DI is also entitled to seek a mid-term review and request enhancement of dumping margin. However, if the current dumping margin is higher than the dumping margin determined in the original investigation, the DI has no option but to suffer for the

period of review. By contrast, the exporter can seek a review of ADD and the importer gets a refund. Thus, no prejudice is caused to exporters.

- ix. It is submitted that during original investigation, the DA has resorted to sampling on the basis of volume of exports made by the responding exporters which proves that relevance and importance of import volumes cannot be undermined for new shipper review case. At this stage, the authority may kindly consider and compare the import volumes that have been reported by responding exporters and compare the same with the import volumes that were reported by responding exporters at the time of original investigations. It would be seen that volume of exports made by these entities are quite low as compared to the volume of exports that were considered for determination of individual normal value and export price on the basis of individual questionnaire response. Thus, the Authority need not determine individual dumping margin on the basis of individual questionnaire response, and respective normal value and export price of the exporters.
- x. It is submitted that since the export price is the price at which goods have been exported for consumption in Indian market, the price at which different buyers in India have purchased the goods from different suppliers from Bangladesh cannot be materially different. For example, if one of the Bangladesh producer is selling at a price of US \$ 1000/ MT, the consumer shall not buy the product from any other supplier at a price materially higher than this price. Thus, there cannot be material difference in the export price of different exporters. Further, while considering the geographical situation of Bangladesh, location of individual Bangladesh plants from Indian ports, there cannot be a material difference in the expenses that have been incurred by different producers in Bangladesh. Thus, in normal competitive situations, there cannot be material difference in export price of different suppliers.
- xi. In view of the above, the DI submits that the authority should restrict the result of present investigations a determination whether the responding exporter constitutes a new shipper within the meaning of Rule 22. If the exporters seeking reviews constitute “new shipper” within the meaning of the Rules, then the Authority may determine dumping margin as the weighted average dumping margin earlier determined for cooperating non-sampled producers. The said dumping margin was determined at the below mentioned levels and therefore we request the authority to kindly fix this quantum of duties for these new shipper entities, subject to the fulfillment of NSR requirement and obligations by these parties. If these parties however fail to satisfy the NSR requirements, in any case, they shall not be entitled to even these dumping margins and these parties should be relegated to the residual duty earlier imposed.

Table showing dumping margin (cooperating non sampled producers) and the duty level
Bangladesh – Dumping Margin and Duty Table

Description of Goods	Producer	Exporter	Dumping Margin Range (%)	Injury Margin Range (%)	Duty Amount
Jute Yarn/ Twine	Non Sampled Producers/ exporters		10-20	20-30	US\$ 97.19/MT
Sacking Bag	Non Sampled Producers/ exporters		10-20	10-20	US\$ 351.72/MT
Hessian Fabric	Non Sampled Producers/ exporters		60-70	40-50	US\$ 125.21/MT

6. The Submissions by Applicant/producer are as under:

- i. The domestic industry has essentially claimed that the authority should restrict the result of present NSR investigations to determination whether the responding exporters constitute a new shipper within the meaning of Rule 22 and if the exporters seeking reviews constitute “new shipper” within the meaning of the Rules, then the Authority may determine dumping margin as the weighted average dumping margin earlier determined for coordinating non-sampled producers. It is respectfully

submitted that the proposal is against the fundamentals of new shipper review as provided in Article 9.5 of the WTO AD Agreement and also Rule 22 of the Indian AD Rules.

- ii. The Agreement and the rules supra clearly says individual margins of dumping for any exporters or producers in the exporting country in question who have not exported the product to India during the period of investigation shall be determined, subject to the qualification provisions. Thus, an individual margin ought to be determined afresh and on older margin cannot be applied on such producers. The apprehension of the domestic industry that the new shippers may get negative dumping margin or the non-sampled categories of exporters will be at disadvantageous position etc. cannot be a ground to deviate from the fundamental aspect of new shipper review which is determination of individual margins of dumping for new shippers as defined in the Rule. Thus, the proposal of the DI to apply not to determine individual margin needs to be rejected as legally untenable.
- iii. The sampling done in the original investigation was based on the circumstances of investigative burden at that point in time and any cherry picking of weighted average margin determined in the then sampled categories for the current new shippers are totally an argument to misguide the Authority and to simply slow down the investigation.
- iv. New shippers are coordinating fully with the Authority and it is requested that individual dumping margins as per the normal value and export price applicable to the concerned new shippers alone may be determined by the Authority.

7. **Withdrawal of Application:**

- i. The Applicant (Exporter) vide its letter dated 10.10.2018 submitted that there are some difficulties due to which our exports of the goods are hindered under consideration to India. The proprietor of the company was hospitalized from 05/07/2018 to 25/09/2018 and the person could not conduct any business as usual during such times. In view of the time lost due to the medical condition as above during which no exports of the goods as per the initiation could be made to India, we requesting the Authority for an extension of POI by another 6 months from 30th September, 2018 with due amendments in the initiation notification so that we could export the goods to India as per the Conditions therein for another 6 months.
- ii. The Applicant (exporter) vide its letter dated 19.11.2018 submitted that in view of the absence of any exports during the POI, we hereby withdraw our NSR application. We understand that with the withdrawal of the application, the case will be terminated by the DA to which we have no objections. Nevertheless, we reserve the rights to approach the Hon'ble Designated Authority in the future.

E. EXAMINATION BY AUTHORITY:

8. The Authority notes that though the DI has made submissions on eligibility and applicability of Rule 22 for the applicant producer/exporter, these are not being addressed as the application has been withdrawn by the Applicant producer/exporter.
9. The Authority notes that the NSR regarding various "Jute products" viz – Jute Yarn/Twine (multiple folded/cabled and single), Hessian Fabric and Jute Sacking Bags was initiated on 23.1.2018 with POI from 1st July, 2017 to 30th September, 2018, for M/s Aman Jute Fibrous Ltd. (Producer), Bangladesh and M/s IB Jute Corporation (Exporter/Trader).
10. The Authority notes that the enabling Custom notification No. 31/2018-Customs (ADD) was issued on 30.5.2018. However the applicant producer/exporter neither exported during the historical POI nor during the prospective POI. The Authority notes that it has been stated that the exporter was unable to undertake exports due to his medical condition. However, the Authority notes that the POI was sufficient enough to enable the producer/exporter to undertake some reasonable exports of Subject goods even though such unavoidable eventualities occurred. It is not the Authority's practice to extend the POI in an NSR investigation at the terminal stage of POI.
11. In view of the unambiguous withdrawal of the petition, the Authority does not consider it appropriate to hold oral hearing and issuing a disclosure, which seems redundant now.
12. The Authority notes that the producer/exporter in its withdrawal letter dated 19.11.2018 have stated that they might approach the Authority at a later date with a similar request.

13. The Authority notes the submission and request of the applicant producer/exporter and other relevant submissions and recommends as under:

- (i) The Applicants M/s. Aman Jute Fibrous Ltd. (Producer) and M/s. IB Jute Corporation (Exporter/Trader) has not exported any subject goods during the POI.
- (ii) In view of (i) above, no individual margin can be recommended for the applicant producer/exporter.
- (iii) The Authority therefore terminates this NSR investigation initiated on 23.1.2018 for the above mentioned producer/exporter. The producer/exporter may file NSR afresh as per provisions of the relevant AD Rules, if they so desire.
- (iv) The Producer/exporter would continue to be assessed as per the Custom Notification No. 11/2017-Customs (ADD) dated 3.4.2017 under the residual category as the case is at present.

SUNIL KUMAR , Addl. Secy. & Designated Authority